(c) the comparative budget and revised estimates in respect of subsidies for the preceeding two years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBIPROSAD PAL): (a) to (c): A statement is laid on the table of the House.

Statement

Statement referred to in reply to Rajya Sabha Starred Question No. 173 for March 12, 1996

(Rupees in crore)

	1993-94		1994-95		1995-96	
	BE	RE	BE	RE	BE	RE
Major subsidies						
Food	3000	5200	4000	5100	5250	5500
Indigenous fertilizers	3000	3800	3500	4000	3750	4300
Imported fertilizers	500	600	500	1166	1650	1935
Export promotion and market development	500	700	300	560	315	315

The main reasons for the increase in RE 95-96 are as follows:—

(i) Food subsidy: Due to non-revision of issue price of foodgrains, clearance of arrears of earlier years and subsidy in respect of levy sugar and imported sugar released through the public distribution system.

(ii) Indigenous fertilizers: The increase is due to higher production of urea and increase in input cost for manufacturing of urea.

(iii) Imported fertilizers: Due to steep rise in international price of urea.

मुद्राओं का गैर-कानूनी लेन-देन

*174. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान अमेरिकी अर्थशास्त्रियों की इस टिप्पणी की ओर दिलाया गया है कि भारत को मुद्राओं के गैर-कानूनी लेन-देन से प्रतिवर्ष 8 अरब डालर का नुकसान हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख) सरकार को डा॰ जॉन डानविक्ज, जो संयुक्त राज्य अमेरीका के फ्लोरिडा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, द्वारा किए गए अध्ययन की जानकारी है। इस अध्ययन के अनुसार, वर्ष 1993 के दौरान भारत से बाहर भेजी गई पूंजी 4422 मिलियन डालर से लेकर 1622 मिलियन डालर के बीच आंकी गई है, जिसे भारत द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका से किए गए आयात और उसको किए गए निर्यात के मूल्यों की तुलना करके औसत में निकाला गया है और औसत संयुक्त राज्य-विश्व आयात एवं निर्यात, मूल्यों के अनुसार समायोजित किया गया है। तथापि, ये 1065 मिलियन डालर से लेकर 370 मिलियन डालर के बीच में है, यदि भारत के आयात और निर्यात मूल्यों की औसत से तुलना की जाती है और संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत के आयात और निर्यात मूल्यों के औसत के अनुसार समायोजित किया जाता है।

इस अध्ययन में भारत से किए गए आयातों अथवा भारत को किए गए निर्यातों के संबंध में केवल संयुक्त

राज्य अमेरिका द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों का प्रयोग किया गया है और उनकी या तो भारत के संयुक्त राज्य अमेरिकी आयात / निर्यात मूल्यों अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका-विश्व आयात / निर्यात मूल्यों के साथ तुलना की गई है। यह तरीका पूंजी के बाह्य प्रवाह का अनुमान लगाने के लिए बिल्कुल त्रुटि रहित नहीं है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं का मूल्य निर्धारण ब्रांड मूल्य, गुणवत्ता, परिमाण, भौतिक विशेषताओं आदि जैसे बहुत से कारकों पर निर्भर करता है और ऐसी परिस्थितियों में औसत का उपयोग करने से भ्रांतिपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।

यद्यपि, अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि वर्ष 1993 के दौरान निर्यातों के कम मूल्य के बीजक बनाने और आयातों के अधिक मूल्य के बीजक बनाने के कारण पूंजी बाहर जाती रही है, तथापि दूसरी ओर निर्यातों के अधिक मूल्य के बीजक बनाने के बहुत सारे मामले भी सरकार के ध्यान में आए हैं।

इसके अतिरिक्त, अध्ययन रिपोर्ट में भारत में किए गए अधिक मूल्य के बीजक वाले आयातों के मदों की निदर्शी सूची से यह पता चलता है कि उसमें उल्लिखित अधिकांश मदों के आयात सामान्यतया हाल में देखने में नहीं आए हैं। पूंजी के बाह्य प्रभाव के अनुमान, जैसे कि अध्ययन में दिए गए हैं, पर इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रख कर विचार किया जाना होगा।

सरकार ने मूल्य की गलत घोषणा करने के मामलों से निपटने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है और सभी सीमा शुल्क प्रचालनों में कम्प्यूटरीकरण की सुविधा लागू करने और आयातों और निर्यातों दोनों के ही मूल्य निर्धारण के संबंध में निर्धारण अधिकारियों की सहायता के उपाय के रूप में मूल्यों की घोषणा को मानीटर करने का प्रस्ताव है।

Implementation of Goiporia Committee recommendations

*175. SHRI VIREN J. SHAH:
SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a report published in the Indian Express of February 19, 1996, under the heading "Flight of deposits threaten Banks", if so, the details thereof;

(b) the details of the recommendations of Goiporia Committee implemented bank-wise and those not yet implemented or partially implemented and the reasons therefor in each case and by when these are likely to be implemented; and

(c) in what way Government propose to achieve the deposit mobilisation target of Rs. 65,000 crores for the current financial year and how much has so far been achieved?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBI PROSAD PAL): (a) and (c) The Report published in the Indian Express dated 19 February, 1996 has been perused. The details of deposits of scheduled commercial banks on different dates are as under:

(i)	As on 5.1.1996	Rs. 406475 crores
	As on 19.1.1996	Rs. 405931 crores
	Decrease	Rs. 544 crores
(ii)	As on 19.1.1996	Rs. 405931 crores
	As on 17.3.1995	Rs. 366698 crores
	Increase	Rs. 39233 crores
(iii)	As on 17.3.1995	Rs. 366698 crores
	As on 21.1.1994	Rs. 307393 crores
	Increase	Rs. 59305 crores

The Following measures have been announced by the Reserve Bank of India (RBI) during the second half of 1995-96 to step up the mobilisation of bank deposits:—

(i) Interest rates on domestic deposits having maturity of over two years have been freed from October 1995.

(ii) The interest rates on deposits under Non-Resident (External) Rupee (NRE) Accounts have been increased from "not exceeding 8.0 per cent" per annum to "not exceeding 10.0 per cent per annum" effective from 1st October, 1995 and further to "not exceeding 12.0 per cent per annum" effective from 31st October, 1995.

(iii) The average Cash Reserve Ratio (CRR) on outstanding net demand